भारत सरकार
परमाणु ऊर्जा विभाग
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या-6137
उत्तर दिनांक 01/04/2026 को दिया गया

दुर्लभ मृदा-तत्व गलियारा

6137. डॉ. कलानिधि वीरास्वामी

क्या प्रधान मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :-

(क) क्या सरकार ने सामान्य बजट 2026 में देश में दुर्लभ मृदा तत्वों की खोज, खनन, प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन को सुदृढ़ करने के लिए समर्पित दुर्लभ मृदा-तत्व गलियारे में स्थापित करने की घोषणा की है;

(ख) यदि हाँ, तो प्रस्तावित गलियारों में चिह्नित खनिज-समृद्ध क्षेत्र, औद्योगिक समूह, अनुमानित वित्तीय आवंटन और कार्यान्वयन समय-सीमा का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इन गलियारों का उद्देश्य आयात पर निर्भरता कम करना तथा इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहन और रक्षा निर्माण जैसे रणनीतिक क्षेत्रों में घरेलू क्षमता बढ़ाना है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या तमिलनाडु राज्य में, विशेषकर तटीय या खनिज-समृद्ध जिलों में प्रस्तावित किसी भी गलियारे की योजना बनाई गई है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा एवं संभावित आर्थिक लाभ क्या हैं;

(ङ) क्या पर्यावरणीय सुरक्षा उपाय, स्थानीय समुदाय से परामर्श और विनियामक मंजूरी को कार्यान्वयन ढाँचे में शामिल किया गया है और यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) इस पहल के अंतर्गत निजी निवेश, प्रौद्योगिकी साझेदारी और डाउनस्ट्रीम विनिर्माण को आकर्षित करने के लिए उठाए गए कदमों का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन तथा प्रधानमंत्री कार्यालय (डॉ. जितेंद्र सिंह)

(क) व (ख) हां, केंद्रीय बजट 2026-27 में ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में समर्पित दुर्लभ मृदा कॉरिडोर की स्थापना की घोषणा की गई है। ये कॉरिडोर खनन, प्रसंस्करण, अनुसंधान और विनिर्माण पर केन्द्रित होंगे, इस प्रकार ये पहलें आत्मनिर्भर भारत, शुद्ध शून्य (नेट जीरो) वर्ष 2070 और विकसित भारत @ 2047 की राष्ट्रीय प्राथमिकताओं के अनुरूप होंगी और भारत का स्थान वैश्विक उन्नत सामग्री मूल्य श्रृंखलाओं में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में उभरेगा।

(ग) हां, ओडिशा, केरल, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु राज्यों में प्रस्तावित दुर्लभ मृदा कॉरिडोर का उद्देश्य आयात निर्भरता को कम करना और रणनीतिक क्षेत्रों में स्वदेशी क्षमता को सुदृढ़ करना है। आरई

कॉरिडोर का उद्देश्य खनन, शोधन और विनिर्माण के लिए एक एकीकृत घरेलू पारिस्थितिकी तंत्र स्थापित करना है। रणनीतिक क्षेत्रों जैसे इलेक्ट्रॉनिक्स, नवीकरणीय ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहनों और रक्षा विनिर्माण में वस्तुओं के उत्पादन के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रमुख खनिजों पर भारत की आयात निर्भरता को, आरई कॉरिडोर के माध्यम से स्थानीय स्रोतों में वृद्धि करके और रणनीतिक आत्म-निर्भरता को सुदृढ़ किया जा सकता है।

(घ) हां, सरकार ने केरल, आंध्र प्रदेश और ओडिशा के साथ-साथ तमिलनाडु राज्य में दुर्लभ मृदा कॉरिडोर स्थापित करने का प्रस्ताव किया है।

(ङ) व (च) सभी हितधारकों का प्रतिनिधित्व करने वाले सदस्यों से युक्त एक संयुक्त कार्य समूह (जेडब्ल्यूजी) का गठन किया जा रहा है, जो निर्धारित राज्यों में समर्पित दुर्लभ मृदा कॉरिडोर स्थापित करने के लिए स्थायी-दिशानिर्देश (एसओपी) तैयार करेगा और जेडब्ल्यूजी एसओपी को अंतिम रूप देने से पहले सभी पहलुओं की जांच करेगा।

*****